भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *201

गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक)

युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी

***201 # श्री रामजी लाल सुमन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के किन-किन निजी क्षेत्रों में वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक बढ़ी है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ हज़ार सरकारी नौकरियों के लिए लाखों आवेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि आईआईटी से उत्तीर्ण युवा भी बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में शहरों और गाँवों में बेरोजगारी दर का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) क्या बढ़ती बेरोजगारी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के संबंध में श्री रामजी लाल सुमन, सांसद द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *201 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): रोज़गार और बेरोज़गारी पर आधिकारिक आँकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2017-18 से आयोजित किया जाता है।

पीएलएफएस की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोज़गारी दर (यूआर) 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति पर रोज़गार (निजी क्षेत्रों सहित) को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है।

इसके अलावा, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है, जो युवाओं की वैश्विक बेरोजगारी दर 13.3% से कम है [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान, 2024 के अनुसार]। इसके साथ ही, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के स्नातक व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.2% से घटकर 2023-24 में 13.0% हो गई है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट में शहरों और गाँवों सहित शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी संबंधी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसे https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है और 27 उद्योगों संबंधी रोजगार अनुमान प्रदान किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अनुमानित रोजगार 2014-15 के दौरान 47.15 करोड़ की तुलना में 2023-24 के दौरान बढ़कर 64.33 करोड़ (अनंतिम) हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 36.44% की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पदों का रिक्त होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेलों का शुभारंभ किया था। अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय स्तर पर 16 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें दस लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।

युवाओं सहित सभी के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इनमें अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंज़ूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता में वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****